Gorakhpur unit of FCI and Haldia Project of HFC was not technoeconomically feasible and revival of these units would require setting up of new plants involving additional investments of Rs. 810 crores and Rs. 910 crores resepctively, it has been decided to consider the option of attracting private capital for their rehabilitation.

The revival package for HFC proposes to offer the Fertilizer Promotion and Agricultural Research Division (FP&ARD) to the State Governments for absorption by them for agricultural extension work.

However, any final decision on the revival packages for FCI and HFC would depend upon the outcome of the proceedings before the BIFR which is quasi judicial authority.

गुजरात में कैल्सियम उर्वरक का उत्पादन

592. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि गुजरात के बहुत बड़े क्षेत्र में केला, गत्रा, मूंगफली आलू तथा बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन फसलों के लिए अत्यधिक मात्रा में कैल्सियम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस राज्य में उन क्षेत्रों में जहां कैल्सियम उर्वरक की अधिक आवश्यकता है, कैल्सियम उर्वरक के उत्पादन हेतु उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती हैं ; और

(घ) इस समय राज्य में उर्वरक का उत्पादन किन –किन कारखानों में कितनी- कितनी मात्रा में हो रहा है

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलोरियों) : (क) 1992-1993 के दौरान

गुजरात में केला, गत्रा , मूंगफली, आलू और बाजरा के क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:-

फसल	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
केला	0.26
आलू	0.16
मूंगफली	18.00
गत्रा	1.25
ज्वार	4.50
बाजरा	12.70
मक्का	3.70
रागी	0.25
महीन बाजरा	0.37

(ख) गत्रा , मूंगफली और आलू के मामले में कैल्सियम की आवश्यकता मुख्य रूप से विविध मृदा में समविष्टा कैल्शियम कारबोनेट से पूरी की जाती हैं। इसलिए, कैल्शियम उर्वरक (जिप्सम/ लाइम) के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं हैं। कैल्शियम के एक भाग की आवश्यकता सिंगल सुपर फास्फेट के उपयोग के माध्यम से पूरी की जाती है। बाजरे तथा केले के लिए कैल्शियम उर्वरक के प्रयोग के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं की जाती हैं।

(ग) मै. कृषक भारती कोआपरेटिव लि, ने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (केन) के उत्पादन के लिए हजीरा, गुजरात मे उर्वरक संयत्र स्थापित करने के प्रस्ताव

को सार्वजानिक निवेश बोर्ड (पी.आई, बी) को द्विचरणीय स्वीकृति प्रकिया के अंतर्गत अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया हैं। 601.38 करोड़ रूपये की अनुमनित लागत पर 2.85 लाख मी. टन प्रति वर्ष (एम टी पी ए) कैन (25/) की तथा नाइट्रोफास्टेट (20.20) की 3.00 लाख मी .टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता बनाने की परियोजना प्रस्ताव में परिकल्पना की गयी हैं। इस परियोजना के लिए प्रथम चरण की मंजूरी प्राप्त हो चुकी हैं।

(घ) गुजरात में विभित्र एककों का उर्वरक उत्पादन का विवरण विवरण में दिया गया हैं

विवरण

गुजरात में उर्वरक एककों का एकक – वार उत्पादन निष्पादन

संयत्र	उत्पाद	उत्पादन (000 मी .टन)	
		1994-95	अप्रैल- अकतूबर 95
नाइट्रोजन एन			
इफको : काण्डला	10.26.26	262.7	91.1
	12.32.16	350.5	174.4
	डी ए पी	424.8	316.7
इफको : कलोल	यूरिया	412.8	240.5
कृभको : हजीरा	यूरिया	1465.8	990.5
जी एस एफ सी : बड़ोदा	यूरिया	360.1	184.1
	ए/ एस	236.5	163.5
	डी ए पी	24.2	6.5
	20:20	242.4	182.9
जी एन एफ सी : भरूच	यूरिया	687.4	404.6
	सी ए एन	143.7	92.1
	20:20	149.3	86.5
जी एस एफ सी : सिक्का	डी ए पी	530.0	344.6
जी एस एफ सी : पालीमेर यूनिट	ए/एस	2.9	5.7
साईनाइड एण्ड केमिकल्स लि.	ए/एस	6.2	0.5
आदर्श केमिकल्स लि. – सूरत	एस एस पी	13.1	-
गुजरात सप्ल. एण्ड लि. अहमदाबाद	एस एस पी	-	-
ग्रोमोर फर्टिलाइजर्स लि. बड़ोदा	एस एस पी	-	-
डी एम सी सी –झार	एस एस पी	33.9	16.9
रामा फर्टिलाइजर्स लि. – जूनागढ़	एस एस पी	41.5	22.5
नर्मदा एग्रो लि.	एस एस पी	0.4	-

Capital Formation in Agricultural Sector

593. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total capital formation in the agricultural sector in each of the years since 1991-92;

(b) the details of such capital formation in the public and the private sectors; and

(c) the measures Government is contemplating to increase the rate of investment in the farm sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) A Statement is annexed. *(See* below).

(c) During the Eighth Five Year Plan (1992—97), significant level of investment has been proposed in favour of areas in Agriculture and Allied Activities like Hotriculture, fishries, rainfed farming and creation of infrastructure for irrigation etc. A new Rural Infrastructural Development Fund within the National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) has been established to encourage investment in the farm sector. Price and trade policies have also been liberalised to create a climate for investment in the agriculture sector.